आकाशवाणी, गोरखपुर

दिनांक–19 नवम्बर 2025 सान्ध्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आज आयोजित 'दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन–दो हजार पचीस' से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इक्कीसवीं किस्त जारी किया। इसके तहत देश भर के नौ करोड़ से अधिक किसानों के खाते में अठारह हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजी गयी। प्रदेश के दो करोड़ पंद्रह लाख से अधिक किसानों को भी इस किस्त का सीधा लाभ मिला है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि बीते ग्यारह वर्षों में, देश के पूरे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा कृषि निर्यात करीब–करीब दोगुना हुआ है। उन्होंने कहा कि खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है।

लखनऊ के कृषि निदेशालय में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में किसान सम्मान निधि की इक्कीसवीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के धन से राज्य के कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में पंचानवे नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने मेरठ, कानपुर और मथुरा–वृंदावन के नगरीय विकास की कार्ययोजना की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी योजनाएं चरणबद्ध ढंग से लागू हों, कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं तथा नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे।

****

अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में ध्वजारोहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ध्वज पताका का दो बार सफल ट्रायल किया जा चुका है।

****

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित वर्ष दो हजार इक्कीस के न्यायाधिकरण सुधार कानून के कुछ प्रावधान रद्द कर दिए हैं। एक रिपोर्ट–

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान केंद्र द्वारा मामूली संशोधनों के साथ फिर से लागू किए जा चुके हैं। पीठ ने कहा कि रद्द किए गए प्रावधानों से शक्ति विभाजन के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा था। पीठ ने कहा कि लंबित मामलों की अधिकता से निपटना न्याय पालिका की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, सरकार को भी यह दायित्व उठाना चाहिए। न्यायालय ने सेवाकाल संबंधी पहले के दिशानिर्देश बरकरार रखे। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयकर अपील अधिकरण तथा सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपील अधिकरण के सदस्य 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में रहेंगे, जबकि इनके अध्यक्ष या प्रमुख 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रहेंगे। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

****

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर कम करने के साथ ही बाइस सितम्बर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे देशभर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। एक रिपोर्ट–

नई जीएसटी सुधार किसानों कारीगरों और छोटे उद्योगों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है काजू उद्योग पर अब सिर्फ 5ः जीएसटी लागू है। इंस्टेंट कॉफी और उसे बनी चीजों पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। मत्स्य पालन और समुद्री प्रोसेस्ड फूड पर जीएसटी घटाकर 5ः कर दी गई है। आयुर्वेदिक दावों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब 5 प्रतिशत कर लगाया गया है जिससे लागत में 6 से 11 प्रतिशत तक की बचत हुई है। इन सुधारो ने प्रमुख क्षेत्रों पर कर का बोझ कम कर दिया है। रिशु जायसवाल और नीतिका गुप्ता के साथ अक्षित वैद्नाथ आकाशवाणी समाचार दिल्ली।

****

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का छप्पनवां संस्करण कल से शुरू होकर अट्ठाइस नवंबर दो हजार पचीस तक गोवा के पणजी में आयोजित होगा। एक रिपोर्ट–

इस भव्य आयोजन में स्क्रीनिंग के साथ–साथ कार्यशालाएं, मास्टरक्लास और फिल्म बाजार आयोजित होंगे, जो देश के नए तथा उभरते फिल्मकारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनियाभर के फिल्मकारों को जोड़ना और कला के माध्यम से मित्रतापूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। इस साल इफ्फी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियन प्रीमियर शामिल हैं। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार पणजी, गोवा।

****

गोरखपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने विशेष गहन पुनरीक्षण–एसआईआर अभियान में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बीएलओ द्वारा दिये जा रहे गणना प्रपत्र को भरवाने में सहयोग करने को कहा।

****

केन्द्र सरकार, उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत वर्ष दो हजार पैंतीस तक ई–पासपोर्ट पूरी तरह से लागू करने पर काम कर रही है। इसके तहत सभी नए जारी पासपोर्ट तत्काल ई–पासपोर्ट बन जाएंगे, जबकि मौजूदा गैर–इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट अपनी समय सीमा समाप्त होने तक वैध रहेंगे।

****